



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—बाण 3—उप-बाण (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 48]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 1994/माघ 13, 1915

No. 48]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 1994/MAGHA 13, 1915

जन-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली 2 फरवरी, 1994

सा.का.नि. 57(ग्र) :—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (सवारी अग्रिम की मंजूरी) विनियम, 1994 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी. आर-12012/23/92-पीई-1]

ग्रामोक जोशी, संयुक्त सचिव

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सवारी अग्रिम की मंजूरी) विनियम, 1994

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वां) की धारा 28 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विद्यमान अग्रिम की मंजूरी के लिए योजना को प्रतिस्थापित करने हुए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

1. संशु प्रीर्व

ये विनियम मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सवारी अग्रिम की मंजूरी) विनियम 1994 के नाम से कहलाएंगे।

2. परिभाषा

इन विनियमों के तहत जब तक कि इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो निम्नलिखित का वही अर्थ होगा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:—

(ए) “अधिनियम” से तात्पर्य है महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963।

(बी) "लेखा अधिकारी" में तात्पर्य है बोई का विन्त मनाड़कार एवं मुख्य लेखा अधिकारी या लेखा विभाग के में श्रव्य अधिकारी जिसे उनकी तरफ से नामित किया गया था।

(गी) "बोई", "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" तथा विभागाध्यक्ष का वही अर्थ होगा जो कि महा पदन त्याग अधिनियम 1963 में दिया है।

(दी) वर्ग 1, 2, 3 और 4 पटों का वही अर्थ होगा जैसा कि समय-नमय पर शोई द्वारा जाने की गई "कर्मचारी अनुसूची" में बताया गया है।

(ई) इन विनियमों के प्रयोजन हेतु "वेतन" में मूल वेतन, शिशेय वेतन, वैयक्तिक वेतन और नौन-प्रेक्टीसियन भन्ता आमिल है।

(एफ) "मंजूरी प्राधिकारी" में तात्पर्य इन विनियमों की संलग्न अनुसूची में निर्धारित किए गए अनुमार होगा।

(जी) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए "अधिम" में तात्पर्य इन विनियमों के तहत संजूर किए गए सवारी अधिम गं है।

३. पात्रता

सभी कर्मचारी जो बोई कर्मचारी अनुसूची में आते हैं वे सभी इन विनियमों के तहत सवारी अधिम की मंजूरी के लिए पात्र होंगे। ये पात्रता ऐसे अधिमों की मंजूरी के लिए निर्धारित की गई शर्तों के तहत होगी :

परन्तु जो कर्मचारी निलम्बन पर हैं ऐसे कर्मचारी निलम्बन की अवधि के दौरान इन विनियमों के तहत सवारी अधिम की मंजूरी के लिए कक्षार नहीं होंगे।

४ मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद के लिए अधिम की मंजूरी

(१) मोटर कार अधिम

(i) इस्ट के सभी अधिकारी जिनका यम वेतन ₹. 3871 और उससे अधिक है मोटर कार की खरीद के लिए मोटर कार अधिम की मंजूरी के लिए पात्र होंगे।

(ii) प्रथम बार मोटर कार खरीदते समय अधिम की राशि ₹. 80,000 या वेतन का 35 गुना या खरीदी जाने वाली मोटर कार का दाम जो भी कम हो।

(iii) दूसरे और/या आगे के समय मोटर कार की खरीद हेतु अधिम की राशि ₹. 75,000 या वेतन का 35 गुना या खरीदी जाने वाली मोटर कार का दाम जो भी कम हो।

(iv) सभी सायनों में मोटर कार की खरीद के लिए मंजूर किए गए अधिम को 200 मासिक बराबर किस्तों में व्यूप्त किया जाएगा जो अधिम लेने के बाद दिए जाने वाले वेतन से काटा जाएगा।

(२) मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड के लिए अधिम

(i) इस्ट के सभी वर्ग 1 व 2 के अधिकारी और वर्ग 3 और 4 के कर्मचारी जिनका वेतन के बाद वेतन ₹. 400 प्र.मा. में कम न हो वा गमय-ममय पर दोई जिस राशि को निर्धारित करता है उसके अनुमार हो, वे मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद के लिए अधिम की भंजूरी हेतु पात्र हैं।

(ii) प्रथम बार मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद के लिए अधिम की राशि ₹. 13000 या 10 महीनों वा वेतन या खरीदी जाने वाली मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड का अनुमानित मूल्य जो भी कम होगी।

(iii) दूसरी बार या आगे के अवसर पर मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद के लिए अधिम की राशि ₹. 10,000 या 8 महीने का वेतन या मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद के लिए अनुमानित मूल्य जो भी कम होगी।

(iv) विनियम 4(2) (ii) और (iii) के तहन मंजूर किए गए अधिम को, अधिम के द्वेष के बाद दिए जाने वाले प्रथम वेतन से 70 मासिक बराबर किस्तों में बाटा जाएगा।

(v) पुरानी मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड को खरीदने के मासिन में ₹. 3,500 या वाहन का वास्तविक मूल्य जो भी कम हो दिया जाएगा और ऐसे मंजूर किए गए अधिम को 60 मासिक बराबर किस्तों में अधिम लेने के बाद के माह में काटा जाएगा।

(३) मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद के लिए अधिम की मंजूरी के लिए जाने

(i) इन विनियमों के विनियम 4 के तहत सवारी अधिम की मंजूरी बजटरी प्रावश्यकों पर होगी और संबंधित विभागाध्यक्ष प्रमाणित करेगा कि संबंधित कर्मचारी द्वारा वाहन रखने पर कार्यालय ड्यूटी के निष्पादन में वक्षता को और वरावा मिलेगा।

(ii) वाहन के वास्तविक मूल्य में बिक्की कर, फास्तू पहिये टावर और ट्यूब का मूल्य और स्कूटर की पिलियन सीट और वाहन के पंजीकरण हेतु अपेक्षित आवश्यक मद्दें आदि आमिल हैं। इसमें श्रव्य उपस्कर जैसे कार में ऐडियो/प्लास्टिक सीट कवर, बीमा और पंजीकरण प्रभार आमिल नहीं हैं।

(iii) अगर वाहन का वास्तविक मूल्य अधिम की राशि में कम हो तो कर्मचारी को उस शेष राशि को एक भुक्त में तुरन्त वापस कर देना चाहिए।

(iv) जिन कर्मचारियों को अधिम की मंजूरी मिल गयी हो उन्हें अधिम प्राप्त करने के पूर्व एक वाण्ड (वंध पत्र) भरना होगा। इसके अलावा उन्हें वाहन को बोई के नाम पर बंधक रखना होगा। अस्थाई कर्मचारी जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा से कम सेवा की हो तो उन्हें इस उपरोक्त के अलावा अगर कार खरीदनी हो तो दो स्थाई कर्मचारियों से गिन्हें

द्रूस्ट की सेवा में 17 वर्ष की अवधि की ओर सेवा करनी हो और मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड खरीदनी हो तो द्रूस्ट में सात वर्ष की सेवा रखने वाले स्थाई कर्मचारियों में जमानत देता हैगी।

(v) सामान्यतः इमरी आर अप्रिम की मंजूरी के लिए कर्मचारी के निवेदन पर विनाश नहीं किया जाएगा । किंतु भी पात्र मामलों में प्राप्त प्राप्ति की दिनांक से बहु वर्ष गार हो किंतु अप्रिम लेने के लिए द्रूस्ट वाले ।

(vi) उस प्रकार या वर्ष के बाहनों की खरीद के लिए दूसरा/बाद की अप्रिम ग्राह्य नहीं होगा जब तक कि पहले और दूसरे अप्रिम की अवधि बम भाल रोकम न हो । और प्रथम अप्रिम में खरीदे गए बाहन को बेच दिया गया है तब यिले अप्रिम के बाबाये को सम्पूर्णतः अदा कर दिया गया है ।

(vii) अगर अधिकारी विभिन्न प्रकार के बाहन अर्थात् मोटर कार और मोटर साईकिल दोनों प्रकार रखना चाहता हो जिसमें एक बाहन द्रूस्ट के अप्रिम से खरीद गया हो और दूसरे प्रकार के बाहन की खरीद के लिए अप्रिम चाहता हो तो पिछले बाहन की बिक्री किए जिस अप्रिम की मंजूरी दी जा सकती है ब्रह्मते कि नया अप्रिम लेने के पहले पिछले अप्रिम की बकाया राशि को व्याज महित बाप्तम लौटा दिया हो । ऐसे मामलों में दिए गए अप्रिम को दूसरे अप्रिम के स्वप्न में माना जाएगा और ऐसे मामलों में विनियम 4(3) (V) में दूसरे अप्रिम हेतु निर्धारित “दस वर्ष की अवधि” बाला प्रतिवेद नापू नहीं होगा ।

(viii) अगर कर्मचारी ने पहले ही बाहन खरीद लिया हो और उसके मूल्य को अर्थात् आर लेकर चुका दिया हो और जब तक बाहन की खरीद की तारीख से तीन माह के भीतर अप्रिम की मंजूरी के लिए आवेदन नहीं करेगा तब तक उसे बाहन की खरीद के लिए अप्रिम की मंजूरी नहीं दी जाएगी ।

(ix) खरीद आर अन्य कार्रवाई की समाप्ति के बाद एक महीने के अंदर कर्मचारी उसी प्रत्येको प्रस्तुत करना चाहिए और अप्रिम लेने की दिनांक में वो महीने के भीतर या अध्यक्ष ब्रारा दो गई भोगता के भीतर बाहन को अध्यक्ष मद्रास पोर्ट द्रूस्ट के नाम पर बन्धक रखना होगा । अगर ऐसा न किया गया तो भुगतान किए गए अप्रिम की सम्पूर्ण राशि को व्याज सहित एक भुगतान में द्रूस्ट को वापस कर देना चाहिए ।

(x) जो कर्मचारी हन विनियमों के नहूत बाहन खरीदते हैं, वे अप्रिम को पूर्णतः वापस नीटानि तक बकाया अप्रिम की राशि के लिए बाहन का दीमा कर देना चाहिए ।

(xi) बिक्री या वदलना

जब तक मोटर कार /मोटर साईकिल/मोपेड की खरीद हेतु लिए गए अप्रिम की राशि सम्पूर्णतः व्याज महित चुका नहीं दी जाती तब तक कर्मचारी बाहन को नहीं बचेगा या किसी और के नाम नहीं बदलेगा ।

(xii) बन्धक पत्र की अभिरक्षा और निपटान बन्धक पत्र का नेत्रा अधिकारों की देव रेत के विरुद्ध जाएगा । व्याज महित अप्रिम को भद्रूषा राशि की बाप्तमी के बाद लेखा अधिकारी बन्धक पत्र पर उन अवधि का पृष्ठाकान करते हुए उसे कर्मचारी को दापस लौटा देगा ।

(5) साईकिल की खरीद हेतु अप्रिम की मंजूरी

(1) सभी वर्ष-3 और 4 के कर्मचारों लिए अप्रिम की दिनांक के आठ वर्ष में प्रथम साईकिल की खरीद हेतु अप्रिम की मंजूरी के लिए पात्र है ।

(2) नई साईकिल के लिए ₹. 1000/- और पुरानी साईकिल के लिए ₹. 600/- अप्रिम दिया जाएगा जिस प्रधिम के प्राप्त करने के बाद के माह से 25 मासिक बराबर किसी में काढ़ा जाएगा ।

(3) विनियम 5(2) के नहूत स्वीकृत अप्रिम संबंधित कर्मचारों को अपनी मर्जी में साईकिल खरीदने के लिए नकद भुगतान किया जाएगा ।

(4) अगर अस्थाई कर्मचारी साईकिल अप्रिम के लिए आवेदन देता है तो वह द्रूस्ट में दो माल की सेवा रखने वाले दो स्थाई कर्मचारियों में जमानत दिखवाएगा ।

(5) द्रूस्ट के अप्रिम से नवीदी गई साईकिल की जद्दी भी निरोत्तर के लिए चाहिए तो कर्मचारी को उसे प्रस्तुत करना चाहिए ।

(6) साईकिल अप्रिम की मंजूरी के लिए व्याज, इन विनियमों के विनियम 6 में निर्धारित व्याज के अनुसार होगी ।

6. व्याज

जो विनियमों के नहूत मोटर कार / मोटर साईकिल / मोपेड / साईकिल की लड़ोद के लिए अप्रिम की मंजूरी पर अप्रिम के वास्तविक भुगतान की दिनांक से साधारण व्याज लगेगा हर माह के अन्तिम दिनांक में धोषभूत बकाया राशि पर ही व्याज की गणना की जाएगी । समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए गंजुर किए गए अप्रिम पर जो व्याज लगता है वही व्याज दर द्रूस्ट के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत अप्रिम पर भी लगाया जाएगा । अप्रिम की मंजूरी के गमय जो व्याज दर लगाया जाता है वही सम्पूर्ण अप्रिम की भुगतान की तिथि तक जारी रहेगा ।

7. सामान्य नस्ते

(1) अप्रिम के आहरण के बाद किसी कारणवश कर्मचारी अप्रिम के आहरण के दिनांक में एक माह के भीतर छहे प्राप्त नहीं कर लेता तो वह अप्रिम मद्रास पोर्ट द्रूस्ट लेखे में पुनः जमा कर दिया जाएगा । निर्धारित समय सीमा के बाद ऐसी राशि को अध्यक्ष दी मंजूरी के माथ पुनः आहरण किया जाएगा ।

(2) जो कर्मचारी अधिकारी की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र में गलत सूचना देते हुए पाये जाएँगे उन पर मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (बर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1988 और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1987 के साथ पटित प्रावधानों के अनुसार दण्ड के भागी होंगे।

(3) विभागाध्यक्ष कर्मचारियों के आवेदन पत्रों/बंधक पत्रों/गिरवी पत्र आदि को अधिकारी की समाप्ति या ममायोजन होने तक अपने पास मुरक्खित रखेंगे।

(4) सेवा निवृत्त या भूतक कर्मचारियों के मामलों में इन विनियमों के तहत स्वीकृत अधिकारी की बकाया राशि को कर्मचारी को देय अविष्य निधि परिसम्पत्ति या सेवा निवृत्त लाभों से काटा जाएगा।

8. फार्म और प्रक्रिया

इन विनियमों के तहत अपेक्षित फार्म जैसे जमानते बंधक, गिरवी बंधक और अन्य फार्मों और प्रक्रिया अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार होंगी।

9. व्याख्या

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में किसी प्रश्न के उल्लेख पर उसे बोर्ड के पास भेजा जाएगा और जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

10. छूट देने के लिए अधिकार

विशेष मामलों में इन विनियमों के किसी प्रावधान में छूट देने का अधिकार बोर्ड को ही है।

11. सरकारी नियमों का लागू करना

इन विनियमों में किसी भी बात के होने हुए भी समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियम के प्रावधान और उस पर सरकारी आवेदों को अपनाया जाएगा जिसके लिए बोर्ड ऐसे संशोधनों या अपवादों पर निर्णय लेगा और सरकारी अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(12) निरसन और बचाव

मौजूदा मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारियों को अधिकारी की मंजूरी के लिए योजना के प्रावधान जो इन विनियमों के लागू होने के पहले थे को निरस्त किया जाता है।

परंतु उपरोक्त निरस्त योजना के प्रावधानों के तहत कोई भी आवेदा दिये हों या कार्रवाई की गई हो तो इन विनियमों के सदृश प्रावधानों के तहत बताई गई या ली गई मानी जाएगी।

11. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवारी अधिकारी की मंजूरी) विनियम

म. पो. द्र. कर्मचारी (सेवारी अधिकारी की मंजूरी) विनियम के तहत विभिन्न प्रकार के अधिकारी की मंजूरी के प्रयोजन हेतु मंजूरी प्राधिकारी

[कृपया विनियम 2(1) देखें]

क्रम सं.	विनियम	अधिकारी की प्रकृति	कर्मचारियों की श्रेणी	मंजूरी प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	4	मोटर कार अधिकारी	विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष से इतर अन्य सभी प्रधिकारी	अध्यक्ष उपाध्यक्ष
2.	4	मोटर साईकिल/स्कूटर/मोटेर अधिकारी	विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष को छोड़ कर सभी वर्ग-1 व 2 प्रधिकारियों के लिए वर्ग-3 और 4 के सभी	अध्यक्ष उपाध्यक्ष
3.	5	साईकिल अधिकारी	विभागाध्यक्ष जिसके तहत कर्मचारी कार्यरत हों। वर्ग-3 और 4 के सभी कर्मचारियों के लिए	विभागाध्यक्ष या प्रभाग प्रधि- कारी अर्थात् विभागाध्यक्ष से एक स्तर कम हो और कर्मचारी उसके अधीन काम करता हो।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 1994

G.S.R. 57(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Madras Port Trust Employees' (Grant of Conveyance Advance) Regulations, 1994 made by the Board of Trustees for the Port of Madras and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No PR-12012/23/92-PE.I]

ASHOKE JOSHI, Jr. Secy.

MADRAS PORT TRUST

MADRAS PORT TRUST EMPLOYEES' (GRANT OF CONVEYANCE ADVANCE) REGULATIONS, 1994

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Madras Port Trust Board hereby makes the following Regulations in replacement of the existing scheme for the advance :

1. Short title : These Regulations shall be called the Madras Port Trust Employees' (Grant of Conveyance Advance) Regulations, 1994.

2. Definition : In these Regulations, unless the context otherwise requires :—

- (a) 'Act' means the Major Port Trusts Act, 1963;
- (b) 'Accounts Officer' means the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Board or such other Officer(s) from the Accounts Department, as may be nominated on his behalf;
- (c) 'Board', 'Chairman', 'Deputy Chairman' and 'Heads of Departments' shall have the meanings respectively assigned to them in the Major Port Trusts Act, 1963;
- (d) Classes I, II, III and IV posts shall have the meanings as defined in the 'Schedule of Employees' issued by the Board from time to time;
- (e) 'Pay' for the purpose of these Regulations shall include basic pay, special pay, personal pay and non-practising allowance;
- (f) 'Sanctioning Authority' for the purpose of these regulations shall be as prescribed in the Schedule attached to these regulations; and
- (g) 'Advance' for the purposes of these regulations shall mean the conveyance advance granted under these Regulations.

3. Eligibility—All employees borne on the Schedule of Employees of the Board shall be eligible for the grant of conveyance advance under these Regulations subject to the terms and conditions stipulated for the grant of such advances.

Provided that employees under suspension are not entitled for the grant of conveyance advance under these regulations during the period of suspension.

4. Grant of advances for the purchase of Motor Car|Motor Cycle|Scooter|Moped :

(1) Motor Car Advance :

- (i) All the Trust's Officers who are drawing a basic pay of Rs. 3871 and above are eligible for the grant of Motor Car Advance for the purchase of Motor Car.
- (ii) The quantum of advance for the purchase of Motor Car on the second and/or subsequent occasions is of pay or the price of the Motor Car to be purchased whichever is the least.
- (iii) The quantum of advance for the purchase of Motor Car on the second and/or subsequent occasions is Rs. 75,000 or 35 times of pay or the price of the Motor Car to be purchased whichever is the least.
- (iv) The advance granted for the purchase of Motor Car in all cases shall be recoverable in 200 equal monthly instalments commencing with the first issue of pay after the advance is drawn.

(2) Motor Cycle|Scooter|Moped Advance :

- (i) All Classes I and II Officers and Classes III and IV employees of the Trust whose take home pay is not less than Rs 400 p.m. or such amount as the Board may fix from time to time are eligible for the grant of advances for the purchase of Motor Cycle|Scooter|Moped.
- (ii) The quantum of advance for the purchase of Motor Cycle|Scooter|Moped on the first occasion is Rs. 13,000 or 10 months pay or anticipated price of the Motor Cycle|Scooter|Moped to be purchased whichever is the least.
- (iii) The quantum of advance for the purchase of Motor Cycle|Scooter|Moped on the second or subsequent occasion is Rs. 10,000 or 8 months pay or anticipated price of the Motor Cycle|Scooter|Moped to be purchased whichever is the least.
- (iv) The advance granted under Regulation 4 (2)(ii) and (iii) shall be recoverable in not more than 70 equal monthly instalments commencing from the first issue of pay after the drawal of advance.
- (v) In the case of purchase of second-hand motor cycle|scooter|moped, the quantum of advance admissible is Rs. 3,500 or the actual price of the vehicle whichever is the least and the amount so granted is recoverable in 60 equal monthly instalments commencing from the first issue of pay after the drawal of advance.

(3) Conditions for the grant of advance for the purchase of Motor Car|Motor Cycle|Scooter|Moped:

- (i) The grant of conveyance advances under Regulation 4 of these regulations is subject to the budgetary provisions and also subject to the Head of Department concerned certifying to the effect that the possession of conveyance by the employee concerned will add to the efficiency in the discharge of his/her official duties.
- (ii) The actual price of the conveyance will include the sales tax, cost of spare wheel, tyre and tube and the pillion seat in the scooter and necessary items required for registration of the vehicle. It will not include accessories like radio in a car|plastic cover seat, insurance and registration charges.
- (iii) If the actual price of the conveyance is less than the advance drawn, the employee shall forthwith refund the excess amount drawn in one lump sum.
- (iv) The employees who are sanctioned the advance shall execute a bond before the advance is received by them. In addition, they should hypothecate the conveyance to the Board. Temporary employees,

who have put in less than five years of service, should in addition, produce a surety bond from two permanent employees of the Trust having a further period of seventeen years of service in the Trust, if the advance to be granted is for the purchase of a car and seven years of further service in the Trust, if the advance to be granted is for the purchase of motor cycle|scooter|moped.

- (v) The request from the employees for grant of second advance shall not be entertained in normal course. However in deserving cases, it shall be entertained only after a period of ten years from the date of drawal of the first advance.
- (vi) Second|subsequent advance for the purchase of the same category or type of vehicle is not admissible unless the period between first and second advance is not less than ten years and the vehicle purchased earlier by availing the advance is sold and the balance of the previous advance, if any is fully liquidated.
- (vii) Where an officer desires to keep two vehicles of different types i.e. a motor car and a motor cycle and has purchased one type of vehicle with the advance drawn from the Trust and wants to have advance for purchasing a different type of vehicle, he/she may be sanctioned the same without being required to set the previous vehicle, provided the officer repays the outstanding amount of advance with interest before drawing fresh advance. An advance given in such a case will be treated as second advance and the restriction of ten years for availing the second advance as stipulated under Regulation 4 (3) (v) above shall not apply in such cases.
- (viii) An advance for the purchase of conveyance will not be granted to an employee who has already purchased a conveyance and paid for it, unless the employee applies for the grant of advance within three months from the date of purchase of the conveyance which has been paid for by raising a temporary loan.
- (ix) After completing purchase and other transactions, the employee should produce all documents within one month and hypothecate the conveyance in favour of the Chairman, Madras Port Trust within two months from the date of drawal of advance or within such extended period as may be allowed by the Chairman, failing which the entire amount paid as advance should be refunded to the Trust together with interest in one lumpsum.
- (x) Employees who purchase the conveyance under these regulations should keep the vehicle insured comprehensively for an amount not less than the outstanding advance till the advance is fully repaid.
- (xi) Sale or transfer : An employee shall not sell or transfer a Motor Car|Motor Cycle|Scooter|Moped so long as the amount of advance together with interest on such amount is completely repaid.
- (xii) Custody and disposal of mortgage bond : The mortgage bond shall be kept in the safe custody of the Account Officer. On repayment of the advance in full, together with the interest due thereon, the Accounts Officer shall make an endorsement to that effect on the bond and return the same to the employee.

(5) Grant of advance for the purchase of Bicycle :

- (1) All Classes III and IV employees are eligible for the grant of advance for the purchase of Bicycle once in eight years from the date of last drawal of advance.
- (2) The quantum of advance for the purchase of a brand new bicycle is Rs. 1000 and for the purchase of a second hand bicycle is Rs. 600 which is recoverable in 25 equal monthly instalments commencing from the first issue of pay after receipt of advance.

(3) The advance sanctioned under Regulation 5(2); above shall be paid in cash to the concerned employee for purchase of cycle at his own choice.

- (4) In the case of temporary employees applying for the grant of cycle advance, the advance will be sanctioned only if the applicant furnishes surety from two permanent employees who have at least two years of future service in the Trust.
- (5) The employees should produce the cycle purchased utilising the advance for inspection as and when required.
- (6) The interest for the grant of cycle advance shall be as prescribed in Regulation 6 of these Regulations.

6. Interest :

The grant of advance for the purchase of Motor Car|Motor Cycle|Scooter|Moped|Bicycle under the Regulation carries simple interest from the date on which the advance is actually paid—the amount of interest being calculated on the balance outstanding on the last date of each month. The rate of interest payable on the advance sanctioned will be the rate at which the Government of India sanction similar advances to their employees from time to time. The rate of interest at the time of sanction of advance will remain unchanged till the advance is fully repaid.

7. General conditions :

- (1) The advances drawn but not received by the employee for any reason within one month from the date of drawal should be credited back to Madras Port Trust Accounts. The redrawal of such amount after the prescribed time limit shall be done with the sanction of the Chairman.
- (2) The employees who are found to have given false declaration in the application form for the grant of advances are liable to be penalised as per the provisions of the Madras Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1988 read with Madras Port Trust Employees' (Conduct) Regulations, 1987.
- (3) The Heads of Departments shall preserve the application forms|surety forms|mortgage bonds etc. of the employees till the advances are liquidated or adjusted.
- (4) In the case of retirement or death of an employee, the outstanding amount towards the grant of advances under these Regulations shall be recoverable from the Provident Fund Assets or retirement benefits due to the employee.

8. Forms and Procedures : The forms such as surety bond, hypothecation deed and other forms required under these regulations and the procedures thereon shall be as prescribed by the Chairman from time to time.

9. Interpretation : If any question arises as to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Board whose decision thereon shall be final.

10. Power to relax : The power to relax any of the provisions of these regulations in exceptional cases shall vest with the Board.

11. Government's Rules to apply : Notwithstanding anything contained in these Regulations, the provisions of the General Financial Rules as amended from time to time and Government Orders thereon shall be adopted with such modifications or exceptions as the Board may decide, with the prior approval of Central Government, pending formal amendment to these Regulations.

12. Repeal and Savings : The provisions of the existing Scheme for the grant of advance to the employee of the Madras Port Trust which were in force immediately before the commencement of these regulations are hereby repealed.

Provided that any order made or any action taken under the provisions of the aforesaid scheme so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

SCHEDULE

MADRAS PORT TRUST EMPLOYEES (GRANT OF CONVEYANCE ADVANCE) REGULATIONS.

Sanctioning Authorities for the purpose of grant of various kinds of advances under the MPT Employees' (Grant of Conveyance Advance) Regulations.

[Please see Regulation 2(f)]

Sl. No.	Regulation No.	Nature of Advance	Categories of employees	Sanctioning Authority
1	2	3	4	5
1.	4	Motor Car Advance	Heads of Departments All other Officers excluding the Heads of Departments.	Chairman Deputy Chairman
2.	4	Motor cycle/Scooter/ Moped Advance	Heads of Departments. All Classes I and II Officers other than Heads of Departments. All Classes III and IV employees.	Chairman Deputy Chairman
3.	5	Cycle Advance	All Classes III and IV employees.	Heads of Departments under whom the employees are working. Heads of Departments or the Divisional Officers one level below the Heads of Departments under whose control the employees are working.

